कुलपति/प्रतिकुलपति सम्मेलन में महामहिम राज्यपाल श्री राम नाथ कोविन्द का संबोधन

(दिनांक–16.05.2017, समय–पूर्वाह्न–10:30 बजे, स्थान–राजभवन, पटना)

माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी, शिक्षा मंत्री श्री अशोक चौधरी जी, प्रधान सचिव डॉ॰ ई॰एल॰एस॰एन॰ बाला प्रसाद जी, शिक्षा विभाग के प्रधान सचिव श्री आर॰के॰ महाजन जी, राज्य के विश्वविद्यालयों के सभी कुलपति एवं प्रतिकुलपतिगण, सम्मेलन में विशेष रूप से आमंत्रित शिक्षाविद् प्रो॰ दीपक नैय्यर जी एवं प्रो॰ पंजाब सिंह जी, शिक्षा विभाग, राज्यपाल सचिवालय एवं विश्वविद्यालयों के अधिकारीगण!

पिछले वर्ष भी कुलपतियों का सम्मेलन राजभवन में आयोजित किया गया था एवं इस वर्ष भी हम यहाँ एकत्रित हैं। उद्घाटन–सत्र में माननीय मुख्यमंत्री जी भी उपस्थित हैं, शिक्षा मंत्री भी हैं –मैं आप सबका स्वागत करता हूँ। मैं समझता हूँ, मुख्यमंत्री जी की आज इस आयोजन में उपस्थिति राज्य में उच्च शिक्षा के प्रति राजभवन एवं राज्य सरकार दोनों की चिन्ताओं के संदर्भ में अत्यन्त महत्त्वपूर्ण एवं फलदायी सिद्ध होगी। शिक्षा मंत्री एवं मुख्यमंत्री जी ने आप सबका बेहतर एवं विस्तार के साथ मार्ग–दर्शन किया है।

मित्रों, यह एक सच्चाई है कि आज हमारे विश्वविद्यालयों का वातावरण वर्तमान शैक्षणिक जरूरतों और छात्रों की उम्मीदों के अनुरूप नहीं है। इसीलिए, हमारे विद्यार्थी बेहतर अवसरों की खोज में बाहर जाने को विवश होते हैं। फलतः हमें ऐसे ठोस उपाय करने होंगे, जिनसे हमारे विश्वविद्यालय ज्ञान, शोध, विद्वत्ता एवं बेहतर अवसर के केन्द्र बन सकें। हमने स्नात्तकोत्तर स्तर पर 'सेमेस्टर पद्धति' लागू की है। कुछ वोकेशनल पाठ्यक्रमों में भी इसे लागू किया गया है, लेकिन इन पाठ्यक्रमों से कुछ रोजगार अवश्य मिल जाता है, लेकिन यहाँ भी हम गुणवत्तापूर्ण शिक्षा दे पाने में सफल नहीं हो पाए हैं। इन बातों को स्वीकार करते हुए हमें जल्दी ही समाधान तलाशने होंगे। बिहार –जहाँ कभी नालन्दा और विक्रमशिला जैसे विश्वप्रसिद्ध विश्वविद्यालय स्थापित थे, के गौरवमय अतीत को हमें नही भूलना चाहिए। हमें अपनी उस गरिमा और Glory (चमक) को पुनः स्थापित करना होगा।

बिहार की भूमि ज्ञान और कर्म की भूमि रही है। एक से बढ़कर एक महाज्ञानी और कर्मयोगी यहाँ हुए हैं। जगत्–जननी माँ सीता, गौतम बुद्ध, महावीर, गुरू गोविन्द सिंह, चन्द्रगुप्त, चाणक्य, आर्यभट्ट, याज्ञवल्क्य, जनक, वराहमिहिर, भारती–मंडन मिश्र जैसे अनगिनत महामानवों की भूमि पर आज भी प्रतिभाशाली युवाओं की कमी नहीं। किसी भी प्रतियोगी परीक्षा में बिहारी युवा अपनी मेधा का

अद्‌भुत प्रदर्शन करते हैं। यहाँ यह बात विचारणीय है कि हम इन युवाओं को अपने विद्यालयों, महाविद्यालयों एवं विश्वविद्यालयों में कैसे बेहतर–से–बेहतर रूप में शिक्षण–सुविधा उपलब्ध करा सकें कि इन्हें अध्ययन के लिए राज्य से बाहर नहीं जाना पड़े। मुझे लगता है शिक्षा एवं चिकित्सा –इन दो प्रक्षेत्रों में हम अगर अपनी आधारभूत सुविधाओं को गुणवत्तापूर्वक विकसित कर लेते हैं, तो हमारे राज्य की बहुत बड़ी पूंजी दूसरे राज्यों में जाने की बजाए हमारे अपने राज्य के आर्थिक सुदृढ़ीकरण में काम आएगी।

राज्य सरकार भी उच्च शिक्षा प्रक्षेत्र को मजबूती प्रदान करने के लिए गंभीर है। लगभग सभी विश्वविद्यालयों में नये कुलपतियों एवं प्रतिकुलपतियों की नियुक्तियाँ हो चुकी हैं। आप सभी नये कुलपतियों व प्रतिकुलपतियों को मैं अपनी बधाई देता हूँ और यह उम्मीद करता हूँ कि आप सभी निर्धारित लक्ष्यों पर पूरी तरह खरे उतरेंगे एवं बिहार को उच्च शिक्षा के क्षेत्र में आदर्श मानकों के अनुरूप विकसित करने में अपनी प्रतिभा और परिश्रम का पूरा सदुपयोग करेंगे।

आपको इस सम्मेलन के संदर्भ में चर्चा के कुछ बिन्दु उपलब्ध कराये गये थे तथा कुछ महत्त्वपूर्ण लक्ष्यों की ओर मुख्यमंत्री जी ने भी आपका ध्यानाकर्षण किया है। मैं कुछ मूलभूत अपेक्षाएँ आपके समक्ष रखना चाहता हूँ। समय से नामांकन, समय से वर्ग–संचालन, समय से परीक्षा– आयोजन, समय से परीक्षाफल का प्रकाशन और ससमय 'दीक्षांत–समारोहों' का आयोजन –यह आपका प्राथमिक लक्ष्य होना चाहिए। मैं समझता हूँ, इसके लिए अपने 'एकेडमिक कैलेण्डर' के सख्ती से अनुपालन में अगर आप सफल हो जाते हैं, तो विश्वविद्यालयों में अध्ययन–अध्यापन का बेहतर माहौल भी स्वतः तैयार हो जाएगा। शिक्षकों की महाविद्यालय या विश्वविद्यालयों में पाँच घंटे उपस्थिति सुनिश्चित करने की दिशा में आपसे पूरी गंभीरता की मैं अपेक्षा करता हूँ और यह उम्मीद रखता हूँ कि इस संबंध में राज्यपाल सचिवालय और शिक्षा विभाग द्वारा समय–समय पर दिये गये पूर्व–निदेशों का आप शत–प्रतिशत अनुपालन करेंगे।

राज्य में एफीलिएटेड कॉलेजों, बी॰एड॰ कॉलेजों, दूरस्थ शिक्षा, वोकेशनल पाठ्यक्रमों और स्ववित्तपोषित पाठ्यक्रमों के नियमित संचालन पर हमें विशेष रूप से ध्यान देना होगा। ये संस्थान यू॰जी॰सी॰ तथा शिक्षा विभाग द्वारा निर्धारित मानकों और शर्त्तों के अनुरूप संचालित होने चाहिए। ऐसे संस्थानों के संचालन में व्यवसायिक नजरिया और आर्थिक शोषण की मनोवृत्ति यहाँ पैर नहीं जमा सके, इसके लिए हम सबको सजग–सचेष्ट रहना होगा।

विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों में नामांकन, निबंधन से लेकर परीक्षाफल– प्रकाशन एवं प्रमाणपत्र–वितरण तक की पूरी व्यवस्था को कम्प्यूटरीकृत ऑन–लाईन कर हम विश्वविद्यालयों के क्रिया–कलापों में पारदर्शिता और नियमितता

ला सकते हैं। इस दिशा में कुछ विश्वविद्यालय गंभीरता से आगे बढ़े हैं, किन्तु यह व्यवस्था सभी विश्वविद्यालयों में इसी वर्ष से लागू करनी है। आर्थिक जगत् एवं हर तरह की सेवाओं को सुगम रूप से उपलब्ध कराने हेतु हम 'डिजिटल युग' की तरफ तेजी से कदम बढ़ा रहे हैं। विश्वविद्यालय तो ज्ञान–विज्ञान के केन्द्र हैं, फिर इनका इस दिशा में पिछड़ना ठीक नहीं होगा। हमें पुस्तकालयों, प्रयोगशालाओं, होस्टल– नामांकन, प्रमाण– पत्रों के प्रमाणीकरण आदि कार्यों को भी ऑन–लाईन करना होगा।

पिछले वर्ष विश्वविद्यालयों में 'Grievance Redressal Cell' बनाने का हमने निर्णय लिया था। इसके फलस्वरूप, मेरे यहाँ आनेवाली शिकायतों में थोड़ी कमी आई है, परंतु अब भी इनका संचालन सफलतापूर्वक विश्वविद्यालयों में नहीं हो पा रहा है। शिक्षकों एवं छात्रों की कुछ शिकायतें अभी भी पहुँचती रहती हैं। शिकायतों का पहुँचना बुरी बात नहीं, किन्तु वे शिकायतें 'बिहार स्टेट यूनीवर्सिटीज एक्ट' के तहत अपील के रूप में आनी चाहिए ना कि अभ्यावेदनों के रूप में। विश्वविद्यालयों में सेवान्त लाभ के मामलों तथा शिक्षकों–कर्मचारियों आदि की नियुक्ति एवं प्रोन्नति आदि से जुड़े मामलों का तो निष्पादन सम्यक् रूप से विश्वविद्यालय स्तर पर ही ससमय हो जाना चाहिए। छात्र–समस्याओं के निराकरण के लिए भी हमें सजग–तत्पर रहना चाहिए। छात्रों के साथ उच्च स्तर पर सक्षम अधिकारी के साथ पारस्परिक चर्चा करने की व्यवस्था बहाल करना जरूरी है। विश्वविद्यालयों में छात्र–संघों के सफल चुनाव करा दिये जाने पर भी हमें गंभीरता से सोचना चाहिए। इससे लोकतंत्र का पाठ अपने अकादमिक परिसर में ही विद्यार्थियों को उपलब्ध हो जाता है तथा विश्वविद्यालय–प्रशासन को भी छात्र–प्रतिनिधियों के सुझाव प्राप्त करने में सहूलियत हो जाती है। सीनेट एवं सिन्डिकेट की नियमित बैठकों के आयोजन से विश्वविद्यालय की विकास–गतिविधियों एवं शिक्षण–व्यवस्था पर सकरात्मक प्रभाव पड़ेगा। छात्रावासों में विधि–व्यवस्था के समुचित संधारण पर हमें विशेष रूप से ध्यान देने की जरूरत है। निर्धारित प्रक्रिया के तहत सुयोग्य अभ्यर्थियों को छात्रावास– आबंटन के साथ–साथ, हमें यहाँ भोजनालय, शौचालय, वाचनालय, कम्प्यूटर लैब सहित अन्य आधारभूत संरचनाओं को सुदृढ़ करना चाहिए।

विश्वविद्यालयों में शिक्षा–व्यवस्था में गुणवत्ता–विकास के लिए हमें 'नैक मूल्यांकन' के लिए भी तत्पर रहना चाहिए। राज्य सरकार ने उच्च शिक्षा क्षेत्र में 'Centre of Excellence' की स्थापना हेतु कदम उठाया है। इस निर्णय के सफल कार्यान्वयन की जरूरत है। राज्य में दो नये विश्वविद्यालय –पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय एवं पूर्णिया विश्वविद्यालय की स्थापना का निर्णय हो चुका है। मैं समझता हूँ, इससे हमारी उच्च शिक्षा–व्यवस्था को और विस्तार मिलेगी।

विश्वविद्यालयों में गुणवत्ता विकास हेतु स्वस्थ प्रतिस्पर्धा जगाने के उद्देश्य से हमने ''कुलाधिपति सम्मान'' प्रदान किये जाने का सुझाव दिया था। आपकी सहमति बने, तो हम इस पर ठोस निर्णय ले सकेंगे। इसी तरह 'दीक्षांत समारोहों' के लिए देशज परिधानों की व्यवस्था पर हमें सर्वसम्मत निर्णय लेना है। आर्यभट्ट सहित कुछ विश्वविद्यालयों ने इस दिशा में कार्यान्वयन शुरू कर दिया है। हमें पूरे राज्य के लिए एक तरह की ही परिधान व्यवस्था लागू करने पर निर्णय लेना चाहिए।

पिछले वर्ष हमने यह निर्णय लिया था कि प्रत्येक विश्वविद्यालय स्वेच्छया निकटवर्त्ती किन्हीं पाँच गाँवों को गोद लेकर वहाँ सभी प्रमुख सरकारी योजनाओं का सफल कार्यान्वयन सुनिश्चित कराने में अपनी सक्रिय सहभागिता निभायेंगे। मुझे बताया गया है कि कुछ विश्वविद्यालयों में इसके लिए प्रारंभिक पहल की गई है। परंतु, अब हमें दृढ़ निश्चय के साथ इस दिशा में सार्थक निर्णय लेना होगा। राज्य सरकार के 'सात निश्चय' और युवाओं के लिए भारत सरकार की 'प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना', 'जन–धन योजना', 'डिजिटल इंडिया', 'मेड इन इंडिया', 'स्वच्छ भारत अभियान' जैसे कार्यक्रमों के इन गाँवों में सफल कार्यान्वयन सुनिश्चित करा विश्वविद्यालय अपने सामाजिक दायित्वों को भी वहन कर सकते हैं।

राज्य की सड़कों की स्थिति में सुधार, विभिन्न सरकारी सेवाओं की त्वरित उपलब्धता, बिजली की हालत में सुधार, शराबबंदी के सकारात्मक प्रभाव आदि कारणों से बिहार की छवि में हुए सुधार की बातें, बाहर में भी हमें सुनने को मिलती हैं। किन्तु, उच्च शिक्षा के क्षेत्र में अभी बहुत कुछ किया जाना शेष है। विश्वविद्यालय शिक्षकों की कमी की समस्या से जूझ रहे हैं। आशा है, 'यूनिवर्सिटी सर्विस कमीशन' का गठन हो जाने पर, शिक्षक–नियुक्ति की प्रक्रिया में तेजी आएगी और विश्वविद्यालयों को इस समस्या से मुक्ति मिल सकेगी।

आइए, हम सब मिलकर बिहार के विश्वविद्यालयों को भी ज्ञान–विज्ञान के एक ऐसे केन्द्र के रूप में विकसित करें, जो आधुनिक मानव के स्वर्णिम सपने को साकार करने की क्षमता रखते हों तथा सत्य और सदाशयता के संकल्पों के साथ मनुष्यता की विजय–यात्रा के सफल ध्वजा–धारी सिद्ध हों। आशा है, सम्मेलन के आगामी तकनीकी सत्रों में विभिन्न विषयों पर सार्थक चर्चाएँ करते हुए आप एक प्रभावकारी निष्कर्ष पर पहुँचेंगे। उच्च शिक्षा के विकास हेतु समेकित 'रोड–मैप' तैयार करने में इससे सुविधा होगी। आप सबको बहुत–बहुत धन्यवाद।

जय हिन्द!!

***